

UnStarred Assembly Question No. 28 (14/15/170)

Survey of Eligible Families

28 (14/15/170) Sh. Mewa Singh (Ladwa):

Will the Chief Minister be pleased to state: -

- a) The number of the families whose ration cards and pensions have been discontinued after issuing Parivar Pehchan Patra in the State; and
- b) whether any survey has been conducted by the Government for the eligible families whose ration cards and pensions have been discontinued together with the details thereof?

Answer: - Sh. Manohar Lal, Hon'ble Chief Minister, Haryana

a) On verification of self-declared data provided by families at the time of registration in Parivar Pehchan Patra, yellow ration cards were discontinued for 9,60,235 families in December 2022. Based on requests for re-verification, ration cards have been re-issued to 1,30,068 families.

Old Age Samman Allowances and other pensions have been withheld for 21,034 citizens only based on verified data in PPP, from May 2022 onwards.

b) The verification of self-declared income in PPP database is done by the following methods:

- (a) through an online system with Central Board of Direct Taxes (CBDT) based on the Income Tax Return (ITR) of the last three years;
- (b) through an online system with Human Resources Management System (HRMS) of data of employees of Government of Haryana, its Boards and Corporations;
- (c) through an online system with data of retired Government pensioners receiving pension or honorarium from Government for service in Government;
- (d) through an online system with data of contractual employees working with the State Government, its Boards and Corporations;
- (e) through an online system with data of wages paid to industrial labour in the private sector in respect of whom a cess is payable under the Punjab Cess Act, as provided by Haryana Labour Welfare Board;
- (f) through an online system based on payments made to farmers for procurement of agricultural produce on e-kharid;
- (g) through an online system based on annual electricity consumption as obtained from the electricity utilities and estimating income thereon;
- (h) through verification of income by Local Committees consisting of five members consisting of Team Lead who is a government employee, a local computer operator, a local volunteer, a social worker and a student. Each of the members independently make an assessment of the income and the final verified income is based on logic-based artificial intelligence.

Families can contest the income verification undertaken in PPP through the designated online mechanisms, namely 'Correction' and 'Grievance' portal including challenges to exclusions. Every exclusion challenge is electronically and automatically pushed to appropriate quarters for online verification. Requests challenging income assessed by Local Committee are pushed to higher level committees called Sector Committees with a similar composition.

अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 28 (14/15/170)

पात्र परिवारों का सर्वेक्षण

28 (14/15/170) श्री मेवा सिंह (लाडवा):

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क) राज्य में परिवार पहचान पत्र जारी करने के बाद कितने परिवारों के राशन कार्ड और पेंशन बंद कर दी गई हैं; और

ख) क्या सरकार द्वारा उन पात्र परिवारों के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है जिनके राशन कार्ड और पेंशन बंद कर दी गई है, साथ ही उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर: - श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा

क) परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण के समय परिवारों द्वारा प्रदान किए गए स्व-घोषित डेटा के सत्यापन पर, दिसंबर 2022 में 9,60,235 परिवारों के पीले राशन कार्ड बंद कर दिए गए थे। पुनः सत्यापन निवेदन पर 1,30,068 परिवारों को पुनः पीले कार्ड जारी किया गए हैं। मई 2022 में पीपीपी में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर केवल 21,034 नागरिकों का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और अन्य पेंशन रोक दी गई है।

ख) पीपीपी डेटाबेस में स्व-घोषित आय का सत्यापन निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है:

(क) पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से;

(ख) हरियाणा सरकार, उसके बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के डेटा का मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) से एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से;

(ग) सरकार में सेवा के बाद सरकार से पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनरों का डेटा एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से;

(घ) राज्य सरकार, उसके बोर्डों और निगमों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों का डेटा का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से;

(ङ) निजी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी के आंकड़ों का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से, जिसके संबंध में पंजाब उपकर अधिनियम के तहत एक उपकर देय है, जैसा कि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है;

(च) ई-खरीदी पर कृषि उपज की खरीद के लिए किसानों को किए गए भुगतान का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(छ) बिजली निगमों से प्राप्त वार्षिक बिजली खपत और उस आधार पर आय का अनुमान लगाने का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(ज) सरकारी कर्मचारी, एक स्थानीय कंप्यूटर ऑपरेटर, एक स्थानीय स्वयंसेवक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक छात्र की टीम से मिलकर बने पांच सदस्यों वाली स्थानीय समितियों द्वारा आय सत्यापन के माध्यम से प्रत्येक सदस्य ने स्वतंत्र रूप से आय का आकलन किया है और अंतिम सत्यापित आय तर्क-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होती है।

पीपीपी में दी गई आय का सत्यापन परिवार नामित ऑनलाइन तंत्र, नामतः 'सुधार' और 'शिकायत' पोर्टल के माध्यम से नाम हटाने को चुनौती दे सकते हैं। प्रत्येक नाम हटाने की चुनौती इलेक्ट्रॉनिक रूप से और स्वचालित रूप से ऑनलाइन सत्यापन के लिए उपयुक्त स्थान पर भेज दी जाती है। स्थानीय समिति द्वारा निर्धारित आय को चुनौती देने वाले अनुरोधों को समान संरचना वाली उच्च स्तरीय समितियों, जिन्हें सेक्टर समितियाँ कहा जाता है, को भेजा जाता है।